साधन आधारित असमानता की समस्या

साभार: लाइव मिंट
(06 अक्टूबर, 2017)

एस. सुब्रमण्यम (अर्थशास्त्री और पूर्व भारतीयसामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के सदस्य)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (भारतीय अर्थव्यवस्था) से संबंधित है।

एकाधिकार बाजार संरचना से गरीब सार्वजनिक स्वास्थ्य परिणामों तक असमानता रोजमर्रा की जिंदगी के कई सारे भागों के नुकसान का कारण बन सकती है।

यदि असमानता के बारे में चिंतित होना आंतरिक नैतिक कारण हैं, तो ऐसी चिंता का साधन आधारित कारण भी हैं। असमानता सिर्फ इसलिए दोषी नहीं है क्योंकि यह स्वाभाविक रूप से अनुचित और अन्यायपूर्ण है, बल्कि इसलिए भी है क्योंकि इससे रोजमर्रा की जिंदगी के कई क्षेत्रों को नुकसान पहुँचता है। इस आलेख में असमानता के इन साधनों में से कुछ एक का एक छोटा सा नमूना या उदाहरण दिया जा रहा है।

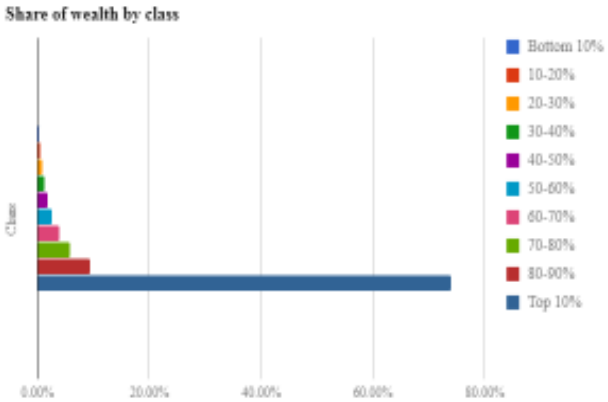

सबसे पहला, राष्ट्रीय आय में वृद्धि की संभावनाओं में असमानता हानिकारक हो सकती है। चूंकि गरीबों को अपनी आय की जरूरतों पर भारी मात्रा में खर्च करना पड़ता है, क्योंकि अमीरों की तुलना में गरीबों के लिए आमदनी का उपयोग करने की सीमांत प्रवृत्ति अधिक है। धन और आय की एकाग्रता में कमी से उम्मीद की जा सकती है कि गरीबों के लिए आय की हिस्सेदारी में वृद्धि हो, जो बदले में उच्च स्तर के खपत को बढ़ावा देगा और इस मार्ग के जरिए, अधिक प्रभावी मांग और बाजारों में गहरा प्रवेश प्राप्त करने में सफल हो पायेगा। आय और निवेश पर एक सम्मिलित सकारात्मक प्रभाव अर्थव्यवस्था में बढ़ती असमानता इन स्वस्थ प्रवृत्तियों को रोकती है।

दूसरा, कुछ के हाथों में धन और आय की एकाग्रता एक बाजार संरचना के लिए अनुकूल होती है, अर्थात एकाधिकारप्राप्त (monopolistic) होती है। मोनोपोलॉजिकल मूल्य निर्धारण, जिसे इसी नाम से अच्छी तरह से जाना जाता है, कल्याण में घातक नुकसान के साथ जुड़ा हुआ है।

तीसरा, अन्य, प्रत्यक्ष तरीके हैं जिसमें असमानता एक अर्थव्यवस्था की दक्षता में हस्तक्षेप कर सकती है। यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि ह्यूग डाल्टन, टोनी एटकिंसन, सर्ज-क्रिस्टोफे कोलम और अमर्त्य सेन जैसे अर्थशास्त्री ने असमानता के द्वारा दक्षता या कल्याण, नुकसान के साथ असमानता का एक उपाय जोड़ा है। विशेष रूप से, अगर आय का मामूली सामाजिक मूल्य आय में बढ़ोतरी के रूप में घट सकता है, तो यह देखना आसान है कि आय के प्रगतिशील पुनर्वितरण में कुल कल्याण बढ़ाना चाहिए और एक समान वितरण को अधिकतम करना चाहिए। समतुल्य रूप से, निश्चित आबादी के लिए औसत आय के किसी भी स्तर के लिए, जिसमें आय असमान रूप से विभाजित है, एक हमेशा निम्न स्तर की आय के बारे में सोच सकता है कि, यदि हर व्यक्ति को इस आय को प्राप्त किया जाता है, तो कुल कल्याण का स्तर समान वितरण के समान होगा, क्योंकि यह पहले असमान वितरण के लिए था।

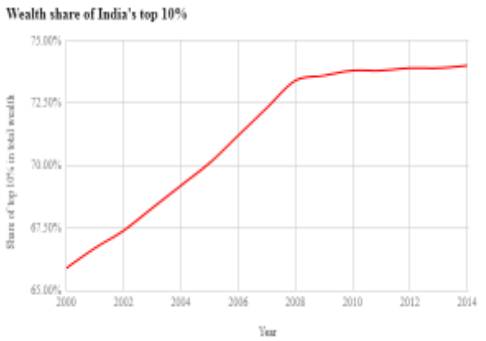

आय के इस स्तर पर एटकिंसन ने इसे 'समान रूप से वितरित समकक्ष' (ईडीई) आय कहा है। वास्तविक औसत आय से ईडीई आय की अनुपात में कमी तो तब कल्याण हानि का एक प्रशंसनीय उपाय है, जिसे बराबर आय शर्तों में मूल्यांकन किया गया है, जो असमानता की उपस्थिति के कारण होता है। देखा जाये तो ऑक्सफोर्ड के दार्शनिक-अर्थशास्त्री जॉन ब्रूम ने इस संबंध में एक अच्छा निबंध लिखा है, जिसका नाम 'द गुड ऑफ इक्विटी' है? जहाँ ब्रूम ने साधन के बजाय, समानता के गुणों पर जोर दिया है, अन्यथा, उन्हें समानता के साथ सही क्या है? नाम से निबंध लिखा जाना चाहिए था। अर्थशास्त्री कौशिक बसु और जेम्स फोस्टर ने दक्षता पर समानता का साधन सकारात्मक रूप से सकारात्मक प्रभाव 'प्रभावी साक्षरता' के एक उपाय द्वारा हाइलाइट किया गया है। वे यह मानते हैं कि साक्षरता एक सार्वजनिक भलाई की तरह है, जैसे साक्षर व्यक्ति अपने परिवार के अन्य सदस्यों पर बाहरी साक्षरता लाभ प्रदान करता है। इस तरह के दृष्टिकोण के अनुसार, साक्षरता के एक अधिक समान अंतर-घरेलू वितरण के साथ समग्र 'प्रभावी साक्षरता' में वृद्धि होनी चाहिए।

चौथा, असमानता अक्सर एक स्रोत और एक दूसरे पर लोगों के एक समूह द्वारा आर्थिक प्रभुत्व का नतीजा है। अर्थशास्त्रियों जैसे देबराज रे, जोन-मारिया एस्टेबैन और अनिर्बान मित्रा ने कार्यों में असमानता और संघर्ष का विषय अच्छी तरह से संबोधित किया है, जब वे ध्रुवीकरण और धार्मिक विभाजनों के आसपास आयोजित संघर्ष की बात करते हैं। वर्ष 2002 की घटनाओं के बाद गुजरात में मुस्लिम समुदाय की आबादी और समुदाय की आर्थिक स्थिति को समाप्त करने का प्रयास, एक बिंदु पर है। प्रासंगिक संसाधनों के अलावा प्राकृतिक संसाधनों के नियंत्रण में आर्थिक असमानताओं द्वारा निभाई गई भूमिका है। येल के नैतिक दार्शनिक थॉमस पॉगे ने बार-बार घरेलू तानाशाहों

द्वारा देश की कमजोरियों में भागित भाग को हाइलाइट किया है जो अपने प्राकृतिक संसाधनों के स्वामित्व को नियंत्रित करते हैं।

पांचवीं, आय और धन की असमानताओं के पास अन्य क्षेत्रों में पहुंच बनाने का एक तरीका है, जैसे स्वास्थ्य। आर्थिक असमानताओं के कारण श्रमिकों पर तनाव और हताशा घेर लेती है। इस तरह असमानता उत्पादकता को कम कर सकती है और इसलिए एक संभावित चक्र में फिर से उत्पादकता को कमाने की क्षमता है। इसके अलावा, एक बहुत ही असमान समाज में अभिजात्य वर्ग सामाजिक क्षेत्र के खर्च के लिए राज्य द्वारा किए गए बजटीय प्रावधानों और कराधान के माध्यम से इसमें वित्तपोषण की बात करते हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य और सार्वजनिक शिक्षा स्वयं के केन्द्रित निहित स्वार्थों की एक प्रणाली की हताहतों की संख्या में होने की उम्मीद हो सकती है जिसे आर्थिक संसाधनों की बड़ी सांद्रता और कुछ लोगों के हाथ में राजनीतिक शक्तियों द्वारा बनाई गई थी। स्वास्थ्य और असमानता के विषय में, बहुत उपयोगी काम ब्रिटेन में माइकल मार्मोट द्वारा और हार्वर्ड अकादमी के इचिरो कवाची तथा एस.वी सुब्रमण्यम द्वारा किया गया है।

यह केवल एक उदाहरण या नमूना पेश किया गया था, जिसके उदाहरण को कई लिंक्स से जोड़ कर देखा जा सकता है। ऐसी प्रवृत्ति विशेष रूप से फासिस्ट प्लूटोकैसीज में चिह्नित हैं और यदि प्रवृत्तियां वह हैं जो हम बोलते हैं, तो हमारे पास भारत की ओर से चिंतित होने का ठोस कारण है।

इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य

विश्व बैंक की रिपोर्ट (एशिया में बढ़ रही शहरी असमानता) : एशिया और प्रशांत क्षेत्र में सबसे ज्यादा अर्बन डेवलप सेक्टर हैं लेकिन इन्हीं देशों में दुनिया की सबसे बड़ी गरीब आबादी (25 करोड़) है। विश्व बैंक ने 'शहरी गरीबों के लिए अवसरों का विस्तार' टाइटल से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि इन भीड़भाड़ वाली कॉलोनियों में रहने वाले लोग पानी, बिजली, टॉयलेट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और आवास की कमी से जूझ रहे हैं।

असमानता की खाई बढ़ी: रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अर्बन डेवलपमेंट ने पिछले 20 सालों में ईस्टर एशिया और प्रशांत क्षेत्र में लगभग 65.5 करोड़ लोगों को गरीबी से उभरने में सहायता की है। लेकिन इसने असमानता की खाई को भी चौड़ा किया है। संगठन ने कहा कि जापान, साउथ कोरिया और सिंगापुर जैसे देशों ने न केवल शहरी बुनियादी सुविधाओं में सुधार कर गरीब लोगों की मदद की है, बल्कि अपनी अर्थव्यवस्था में ग्रोथ में भी योगदान दिया है।

विश्व बैंक की रिपोर्ट (भारत में शिक्षा का स्तर): विश्व बैंक की रिपोर्ट ने भारत की शिक्षा प्रणाली की पोल खोल कर रख दी है। विश्व बैंक की इस रिपोर्ट में दुनिया के 12 ऐसे देशों की सूची जारी की गई है, जहां की शिक्षा व्यवस्था सबसे बदतर स्थिति में है, इस सूची में भारत का स्थान दूसरे नंबर है, जबकि मलावी पहले पायदान पर है।

विश्व बैंक की यह सूची निम्न और मध्य आय वाले देशों के अध्ययन के नतीजे के आधार पर तैयार की गई है। इस अध्ययन में विश्व बैंक ने कहा है कि बिना ज्ञान के शिक्षा देना विकास के अवसरों को बर्बाद कर देता है। यह ना सिर्फ विकास के अवसर को रोकता है बल्कि दुनियाभर के बच्चों और युवाओं के साथ बड़ा अन्याय है। विश्व बैंक की इस ताजा रिपोर्ट में वैश्विक शिक्षा में ज्ञान के संकट की चेतावनी दी गई है, साथ ही कहा गया है कि इससे लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि गिरती शिक्षा व्यवस्था से युवाओं के जीवन में अवसर की कमी और कम वेतन का खतरा मंडराता है, इसकी बड़ी वजह है शिक्षण संस्थान छात्रों को प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में बेहतर शिक्षा मुहैया नहीं करा रहे हैं और यह पूरी तरह से विफल हैं।

रिपोर्ट के अनुसार दूसरी कक्षा के छात्र किताब का एक शब्द तक नहीं पढ़ सकते हैं। विश्व बैंक की इस रिपोर्ट में 'वर्ल्ड डेवेलपमेंट रिपोर्ट 2018- लर्निंग टू रियलाइज एजूकेशंस प्रॉमिस' में कहा गया है कि ग्रामीण भारत में कक्षा तीन के छात्र मामूली सवाल भी नहीं कर सकते हैं। तीसरी कक्षा के तीन चौथाई छात्र मामूली दो अंकों के घटा-जमा के सवाल तक नहीं कर सकते हैं। यही नहीं पांचवीं कक्षा के पचास फीसदी छात्र भी दो अंको का जोड़ घटा नहीं कर पाते हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि बिना ज्ञान की शिक्षा से गरीबी को मिटाने और समाज में समृद्धि लाने के सपने को पूरा नहीं किया जा सकता है, कई सालों तक इन स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों बच्चे पढ़-लिख नहीं पाते हैं, वह गणित के आसान सवाल भी नहीं कर पाते हैं। ऐसे में ज्ञान का यह संकट सामाजिक खाई और असमानता को घटाने की बजाय और बढ़ा रहा है।

विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष जिम योंग किम ने कहा कि ज्ञान का संकट नैतिक और आर्थिक दोनों तरह का है, अगर लोगों को अच्छी शिक्षा दी जाती है तो वह बेहतर नौकरी, आय और स्वास्थ्य का लाभ हासिल करते हैं, अन्यथा गरीबी में जीवन यापन करते हैं। रिपोर्ट में ज्ञान के गंभीर संकट को हल करने के लिए विकासशील देशों की मदद करने के लिए ठोस कदम उठाने की सिफारिश भी की गई है।

संभावित प्रश्न

''वर्तमान में असमानता ही देश में सबसे बड़ी समस्या है। सामाजिक असमानता, आर्थिक असमानता, शैक्षिक असमानता, क्षेत्रीय असमानता और औद्योगिक असमानता ही देश को विकसित बनाने में सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है।'' इस कथन के संदर्भ में इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार द्वारा उठाए जाने वाले अपेक्षित उपायों की चर्चा कीजिए।

Inequality is currently the biggest problem in the country. Social inequality, economic disparity, educational inequality, regional inequality and industrial inequality have created a major hindrance in the countries development. In the context of the above statement discuss the expected measures taken by the government to remove these problems. (200 WORD)